हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 11 अंकः 127 लखनऊ, शनिवार 27 दिसम्बर 2025 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

सुधारों की रफ्तार और होगी तेज, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, जीवन सुगमता पर फोकस

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 'जीवन सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए उसका सुधार अभियान आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सुधार पहलों पर किए गए कई पोस्ट के संदर्भ में यह टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा, ''हमारी सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और नीचे दिए गए लेख में हमने इस दिशा में किए गए कार्यों के उदाहरण दिए हैं। आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेगी।'' हैशटैग ''रिफॉर्म इन एक्शन और हैशटैग गुड गवर्नेंस'' के साथ केंद्र सरकार ने अपने कई पोस्ट में कहा कि किसी भी सुधार की असली कसौटी यह होती है कि वह लोगों का बोझ कितना कम करता है। वर्ष 2025 में शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, जहां सुधार जटिलता के बजाय परिणामों पर केंद्रित रहे। माई जीओवी इंडिया' पर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि सरल कर कानूनों, तेजी से विवाद निपटान, आधुनिक श्रम संहिताओं और कुछ नियमों या कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर सिर्फ उनके अनुपालन पर जोर देने से नागरिकों और व्यवसायों, दोनों के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं। भरोसे, पूर्वानुमेयता और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है, जिससे यह दिखता है कि अच्छी तरह तैयार की गई नीतियां किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी को सहज बना सकती हैं। पोस्ट में कहा गया है कि करोड़ों भारतीयों के लिए कर राहत अब वास्तविकता बन गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर लगता है। मध्यम वर्गीय परिवार अब अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा अपने पास रख पा रहे हैं, जिससे उन्हें खर्च, बचत और निवेश करने के साथ अधिक आत्मविश्वास मिला है। पोस्ट में कहा गया कि आयकर अधिनियम, 2025 ने अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और प्रत्यक्ष कर प्रणाली में स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई है, जिससे यह करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनी है। सरकार ने बताया कि छोटे व्यवसाय अब लाभ खोने के डर के बिना विस्तार कर सकते हैं। निवेश

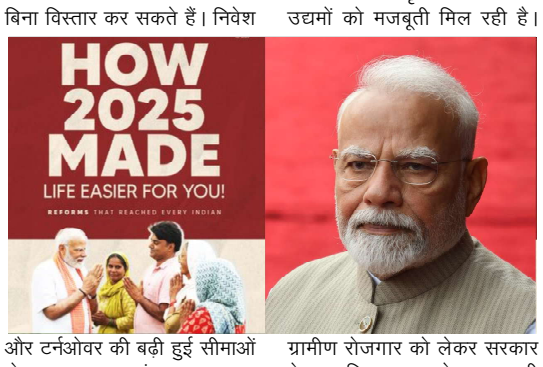

और टर्नओवर की बढ़ी हुई सीमाओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऋण और कर प्रोत्साहनों का लाभ बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इससे व्यवसायों का विस्तार, अधिक रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिल रही है।

ग्रामीण रोजगार को लेकर सरकार ने कहा कि अब यह केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति का निर्माण भी कर रहा है। सुनिश्चित रोजगार की अवधि बढ़ने और गांवों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से ग्रामीण श्रमिक स्थायी परिसंपत्ति बना रहे हैं, जो समुदायों और आजीविका को सशक्त करती हैं। सरकार ने यह भी बताया कि श्रमिकों को अब दर्जनों कानूनों से नहीं जूझना पड़ता क्योंकि 29 श्रम कानूनों को चार सरल संहिताओं में समाहित किया गया है, जो वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को कवर करती हैं। इन सुधारों से अधिकार अधिक स्पष्ट हुए हैं, अनुपालन आसान हुआ है और महिलाओं को मातृत्व तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े सुनिश्चित लाभ मिले हैं। सरकार ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को भी व्यवसायों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए सरल बनाया गया है। सरलीकृत कर स्लैब, आसान पंजीकरण, स्वचालित प्रक्रियाएं और तेज रिफंड के जरिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार व्यापार सुगमता को बेहतर बना रहे हैं। इसका प्रभाव दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री (6.05 लाख करोड़ रुपये) और पिछले एक दशक में सबसे मजबूत नवरात्रि खरीदारी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अब व्यवसाय अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में ला सकते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के युक्तिकरण से भारतीय निर्माताओं के अनुपालन खर्च कम हुए हैं, दक्षता बढ़ी है और वैश्विक बाजारों में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। सरकार ने बताया कि छोटी कंपनियों की परिभाषा का विस्तार किए जाने से अनुपालन बोझ और लागत में कमी आई है, जिससे 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यम नवाचार और विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं।

साहिबजादे मजहबी कट्टरता के खिलाफ साहस की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं : पीएम मोदी

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों (पुत्रों) का सर्वोच्च बलिदान क्रूर मुगल सल्तनत के खिलाफ भारत के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जो भारत के अदम्य साहस, वीरता और शौर्य के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, ''आज हम अपने राष्ट्र के गौरव, वीर साहिबजादों को याद करते हैं। वे भारत के अदम्य साहस और शौर्य के सर्वोच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। उन वीर साहिबजादों ने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया। वे क्रूर मुगल सल्तनत के

खिलाफ चट्टान की तरह ऐसे खड़े रहे कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिल गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हों, वह राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादे उस समय काफी युवा थे, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब की क्रूरता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, ''औरंगजेब जानता था कि यदि वह भारत की जनता में भय उत्पन्न करना चाहता है और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले भारतीयों का मनोबल तोड़ना होगा। इसीलिए उसने साहिबजादों को अपना निशाना बनाया। लेकिन औरंगजेब और उसके सिपहसालार यह भूल गए थे कि हमारे गुरु साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तपस्या और त्याग के साक्षात अवतार थे।''मोदी ने कहा कि माता गुजरी जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और चारों साहिबजादों का साहस और आदर्श प्रत्येक भारतीय को शक्ति प्रदान करते रहते हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 18 राज्यों के 20 प्रतिभाशाली बच्चों को किया सम्मानित

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 राज्यों के 20 साहसी बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुर्मु ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में एक समारोह में इन बच्चों के उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। राष्ट्रपति ने पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मान पाने वाले इन बच्चों से देश के अन्य सभी बच्चे प्रेरित होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व, सिख पंथ के दसवें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिन्द सिंह जी और उनके चारों बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था। इस दिन हम सब उनके दो सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं जिनकी वीरता का सम्मान देश–विदेश में किया जाता

है। मुर्मु ने कहा मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग–अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिये हैं। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवोचार, विज्ञान तथा तकनीकी, समाज–सेवा और खेल–कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल–प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी. ने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाकर अत्यंत प्रशंसनीय काम किया है। इसी तरह से नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि यह गौरव की बात है कि दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अत्यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा–समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्थापित किए। श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान के मन से अब तक नहीं गया ऑपरेशन सिंदूर का डर, सीमा पर लगाए एंटी–ड्रोन सिस्टम

एजेंसी

नयी दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर कई हवाई हमले करते हुए उसे बुरी तरह पराजित किया था। उस हार का भय पाकिस्तान के मन से जा नहीं रहा है। अब उसने एलओसी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे भारत अगली बार हवाई हमले करता है तो उसे कुछ सोचने–समझने का समय मिल सके। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के चीनी एंट्री ड्रोन सिस्टम बिल्कुल काम नहीं किए थे और भारत ने जहां चाहा था। वहां हमला किया था। पाकिस्तान ने एलओसी के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के आगे वाले इलाकों में एंट्री ड्रोन की तैनाती को बढ़ाया है। उसने रावलकोट, कोटली, भीमबर सेक्टर पर नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी–यूएएस) लगाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 30 डेडीकेटेड एंटी–ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं। इसके जरिए पाकिस्तान अपने एयरस्पेस को बेहतर करने में लगा हुआ है।पाकिस्तानी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक और काइनेटिक काउंटर यूएएस सिस्टम का मिक्स लगाया है। इसको लेकर दावा किया जाता है कि यह दस किलोमीटर की रेंज में आने वाले छोटे या फिर बड़े ड्रोन का पता लगा सकता है। हालांकि, यह युद्ध के समय कितना काम आएगा, यह तो समय पर ही पता चलेगा। वहीं, पाकिस्तान सफराह एंटी यूएवी जैमिंग गन का भी इस्तेमाल करता है, जिसे कंधे से चलाया जाता है और आसानी से डेढ़ किलोमीटर की रेंज में आने वाले ड्रोन को मार गिराया जा सकता है।

गडकरी का बड़ा ऐलानः 2026 में खुलेंगे ये सुपर एक्सप्रेसवे

एआई–फासटैग से बाधारहित होंगे टोल, 1.8 लाख मौतें रोकने पर फोकस

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, बाधारहित टोलिंग को लागू करना और एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक पारित कराना 2026 में सड़क परिवहन मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकताएं होंगी। मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने पर खासतौर से जोर दे रहा है। इस समय सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगले साल उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की एक प्रभावशाली सूची तैयार की है। इनमें लंबे समय से लंबित 1,362 किलोमीटर लंबा दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (नवंबर 2026 तक पूरा होगा), अमृतसर–जामनगर राजमार्ग (दिसंबर 2026 तक), बेंगलुरु–चेन्नई एक्सप्रेसवे (जून 2026 तक), अहमदाबाद–धोलेरा एक्सप्रेसवे (मार्च 2026 तक), इंदौर–हैदराबाद राजमार्ग (मई 2026 तक) और दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (जनवरी 2026 तक) शामिल हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक साक्षात्कार में कहा, हम देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, बाधारहित टोलिंग प्रणालियां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। शुरुआती तौर पर इसके लिए हमने 10 निविदाएं निकाली हैं। टोल संग्रह की लागत वर्तमान में कुल टोल संग्रह के लगभग 15 प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत तक आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सालाना 50:60 हजार करोड़ रुपये का टोल संग्रह होता है, तो साल में लगभग 8,000 करोड़ रुपये तक की

बचत हो सकती है। इससे खामियां भी दूर होंगी और टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय भी घटेगा। यह नई प्रणाली एकीकृत प्रौद्योगिकियों के उपयोग से बाधारहित टोलिंग को बढ़ावा देती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और आरएफआईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली फास्टैग शामिल है। सड़क सुरक्षा के बारे में गडकरी ने कहा कि मंत्रालय एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक तैयार करेगा, जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम लगातार सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें कई समस्याएं हैं। हम फिर से प्रयास करेंगे और एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक लाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसे अगले ही सत्र में संसद के समक्ष रखा जाए। गडकरी ने यह भी कहा कि 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग परियोजना, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है।

30 करोड़ की संपत्ति और पाकिस्तानी कनेक्शन, शम्सुल हुदा खान पर ईडी ने कसा शिकंजा

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने ब्रिटेन में रह रहे उत्तर प्रदेश के इस्लामी उपदेशक शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, खान पर पाकिस्तानी संगठन सहित कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की प्राथमिकी पर आधारित है। संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक, खान को 1984 में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि उसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन

इसके बावजूद 2013 से 2017 के बीच विदेश में रहते हुए भी वेतन लेता रहा, जबकि उस अवधि में वह न तो भारतीय नागरिक था और न ही शिक्षण कार्य कर रहा था। खान से इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका है। जांच में यह भी सामने आया है कि खान ने पिछले 20 वर्षों में कई देशों की यात्राएं कीं और सात से आठ भारतीय बैंक खातों के जरिए कथित तौर पर धन प्राप्त किया। अधिकारियों के अनुसार, खान ने करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 12 अचल संपत्तियां भी कथित तौर पर अर्जित की हैं। उस पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ जिले के मूल निवासी खान ने अपने गैर–सरकारी संगठन 'राजा फाउंडेशन' तथा निजी बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर विभिन्न मदरसों को धन पहुंचाया। उस पर आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे स्थापित करने का भी आरोप है, जिनके पंजीकरण बाद में रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन स्थित कट्टरपंथी संगठनों से उसके संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, खान के पाकिस्तान दौरे की भी जानकारी सामने आई है और अधिकारियों का आरोप है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन 'दावत–ए–इस्लामी' का सदस्य है।

दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सेंगर की सजा निलंबन के विरोध में लगाए नारे

एजेंसी

नयी दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां सहित महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ दिनों बाद किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां हाथ में लेकर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के समर्थन में "बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो" जैसे नारे लगाए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) की कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां के साथ मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पीड़िता की मां ने 'पीटीआई–भाषा' से कहा कि वह अपनी बेटी के साथ हुए

अन्याय के विरोध में यहां आई हैं। उन्होंने कहा, "मैं पूरे उच्च न्यायालय को दोष नहीं देती, लेकिन दो न्यायाधीशों के फैसले से हमारा भरोसा टूट गया है और मुझे गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले न्यायाधीशों ने उनके परिवार को न्याय दिलाया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत दे दी गई है। पीड़िता की मां ने कहा, "यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सेंगर की सजा के खिलाफ दायर अपील के निपटारे तक उसे जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया था।

सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा- माघ मेले में मुख्य स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाए

संवाददाता

लखनऊ। प्रयागराज में होने वाले माघ मेला–2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिया कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल न दिया जाए। इन संबंध में आवश्यक सूचना जारी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 15 से 25 लाख श्रद्धालु केवल कल्पवासी होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था या असुविधा न हो। माघ मेले से जुड़े सभी विभागों के प्रमुख सचिव–सचिव स्तर के अधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था खुद मेला क्षेत्र जाकर तैयारियों की समीक्षा करें। 31 दिसंबर तक मेले की सारी तैयारी पूरी कर ली जाए। बैठक में मंडलायुक्त प्रयागराज ने बताया कि माघ मेला का आयोजन 3 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 44 दिनों तक होगा। इस दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख स्नान पर्व पड़ेंगे। पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। जबकि मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख पर्व पर एक ही दिन में साढ़े तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। इसके अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नगर विकास विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ताकि गंगा–यमुना की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से समय से काम पूरा करें। उन्होंने कहा कि माघ मेला ऐसा आयोजन बने, जिसमें आस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन सभी का संतुलित और प्रभावी स्वरूप दिखाई दे। एआई आधारित सर्विलांस से होगा भीड़ व सुरक्षा प्रबंधन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का अधिकतम प्रयोग करें। उन्होंने ट्रैफिक व भीड़ मैनेजमेंट के लिए ठोस और बहुस्तरीय योजना बनाने के निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मेला क्षेत्र में एआई आधारित सर्विलांस व भीड़ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के बेहतर व्यवहार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट के सहयोग लेने साथ ही नाविकों के साथ संवाद और समन्वय बनाने, खान–पान व विभिन्न सेवाओं के शुल्क को नियंत्रित रखने के निर्देश भी दिए। पहली बार ऐप आधारित बाइक टैक्सी, क्यूआर कोड मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेला को सुविधाओं और तकनीक के स्तर पर एक नया मानक बनना चाहिए। बैठक में बताया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा, दिशा सूचक संकेतों की व्यवस्था, विद्युत पोलों पर क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए रिंग मेन यूनिट, कटाव रोकने के लिए जियो–ट्यूब तकनीक आदि लागू की जा रही हैं। स्वच्छता पर विशेष फोकस, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जोर देते हुए कहा कि माघ मेला स्वच्छता का उदाहरण बने। बैठक में जानकारी दी गई कि मेला क्षेत्र में 16,650 शौचालयों की स्थापना की जा रही है। लगभग 3300 सफाई मित्रों की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। उनके लिए सैनीटेशन कॉलोनी, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले में कार्यरत स्वच्छताकर्मियों के मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिन के अंदर कर दिया जाए।

संपादकीय

सरसों का संकट

एक समय था जब पंजाब के ग्रामीण अंचलों में खिले हुए सरसों के खेत मौसमी बयार में बदलाव के प्रतीक हुआ करते थे। तमाम सांस्कृतिक प्रतिमानों में पीले सरसों के खेतों को मौसम के गौरव के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन वक्त की विडंबना है कि यह अब यह सुनहरी फसल सिमटती नजर आ रही है। जिसके परिणाम स्वरूप आज देश में हम खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारत लगातार आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। निश्चय ही यह स्थिति व्यवस्था के कई विरोधाभासों को भी उजागर कर रही है। यह तथ्य चौंकाता है कि पंजाब में सरसों के उत्पादन में इसलिए गिरावट नहीं आ रही है कि फसल उत्पादन क्षमता में किसी तरह की कोई कमी आई है। बल्कि यह स्थिति इसलिए है कि सरकारों की नीतियां प्रोत्साहन देने वाली साबित नहीं हो रही हैं। वहीं बाजार के रुझान इसे आर्थिक रूप से किसानों के हितों के प्रतिकूल बना रहे हैं। कहने को तो अकसर दलील दी जाती है कि पंजाब के किसानी से जुड़े संकटों का समाधान फसलों के विविधीकरण में निहित है। लेकिन विडंबना यह है कि विविधीकरण के दावों के बावजूद, सरसों के उत्पादक किसान प्रोत्साहन न मिल पाने से निराश हैं। दरअसल, किसान कम और अनिश्चित मुनाफे के चलते सरसों की फसल उगाने से गुरेज करता है। उसके सामने बड़ी चुनौती यह भी है कि सरसों की फसल की सरकारी खरीद सीमित मात्रा में होती है। जिसके चलते किसानों को खून–पसीने की उपज को बेचने के लिये व्यापारियों के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने मोटे मुनाफे के लिये किसान के हितों की अनदेखी करने से नहीं चूकते। यही वजह है कि गेहूं और धान के विपरीत, जिनकी खरीद सुनिश्चित है और उनके लिये मजबूत विपणन प्रणाली मौजूद है, सरसों की फसल किसानों को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना देती है। फलतः किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल, इस संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब आज अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का एक मामूली हिस्सा ही स्थानीय उत्पादन से पूरा करता है। इससे हमारी महंगे आयात पर निर्भरता और भी बढ़ जाती है। तिलहन की खेती को बढ़ावा देना अक्सर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही मायनों में सरकारी तंत्र द्वारा सरसों की उपज की खरीद में सहायता और न्यायसंगत मूल्य दिलाने के वायदे खोखले साबित होने के कारण सरसों की पैदावार का रकबा बढ़ता नहीं है। जिस दिन किसानों को तंत्र की नीतियों पर भरोसा पैदा हो जाएगा, उस दिन निश्चय ही किसान प्रोत्साहन के चलते तर्कसंगत प्रतिक्रिया देंगे। निर्विवाद रूप से पंजाब की धरती में सरसों उत्पादन की स्थितियों से जुड़ी संभावनाएं पर्याप्त हैं। यकीनी तौर पर यह धान की तुलना में कम पानी की खपत करती है। साथ ही भूजल संकट को कम करने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण से जुड़ी रणनीतियों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठती है। लेकिन हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि पंजाब में विविधीकरण के लक्ष्य केवल नैतिक प्रोत्साहन से हासिल नहीं किए जा सकते। निश्चित रूप से इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि बाजार की संरचना में जरूरत के अनुरूप बदलाव प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। सही मायनों में सरसों के लिये एमएसपी समर्थित खरीद और स्थानीय प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य शृंखलाओं में निवेश किसानों को सरसों की खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है। यही प्रयास पंजाब के खेतों में पीली आभा फिर से पैदा करने की दिशा में कारगर साबित होंगे। सही मायनों में पंजाब में सरसों की खेती की कहानी नीतिगत विसंगतियों को ही उजागर करती है। दरअसल, संस्थागत स्तर पर समर्थन कुछ चुनिंदा फसलों को दिया जाता रहा है। जब तक यह असंतुलन दूर नहीं किया जाता, सरसों एक खोये हुए अवसर का प्रतीक बनकर रह जाएगी। इस फसल के पुनरुद्धार के लिये महज नारों की ही नहीं, बल्कि उसी गंभीरता की आवश्यकता है, जो गेहूं और धान की फसलों को लेकर लंबे समय से बरती जाती रही है।

राशिफल

मेष :– आज कुछ अच्छे आसारों से मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजगार संबंधी यात्रा में अवरोध संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार है। शिक्षा क्षेत्र में जुड़े सभी छात्रों को परिश्रम करने की आवश्यकता है।

बृषभ :– स्वयं पर भरोसा कर योजनाओं को सुचारु रूप से क्रियान्वित करें। संबंधों में सरल व व्यवहारिक बनने की कोशिश करें। आर्थिक चिंता संभव। शिक्षार्थियों के लिए विशेष लाभ के आसार हैं।

मिथुन :– किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध मन को हतोत्साहित करेगा। संबंधों के प्रति नयी शिकायतें संभव। किसी विद्वान के विचारों से प्रभावित मन मे उत्साह का संचार होगा। क्रोध पर नियंत्रणरखें।

कर्क :– कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्रश्रिम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। पत्नी के स्वास्य का ध्यान रखें।

सिंह :– किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।

कन्या :– समस्याओं के समाधान हेतु मन नए युक्तियों पर केन्द्रित होगा। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न करें। छोटी–छोटी बातों पर क्रोधित न हो। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा।

तुला :– मन सकारात्मक विचारों से प्रभावित होगा। नाजुक संबंधों में सन्तुलित व मधुर वाणी का प्रयोग करें। कोई आपका अपना बिगड़े हुए सम्बन्धों मे सुधार कराएगा। किसी कार्य से संपन्न होने के आसार हैं।

वृश्चिक :– सभी प्रकार के दायित्वों की पूर्ति हेतु सन्तुलित योजना पर चलें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में संबंधों का सहयोग प्राप्त होगा। विरोधियों की प्रबलता से कठिनाइयां संभव। मधुर वाणी का प्रयोग करें।

धनु :– नए समीकरण लाभकारी कार्य क्षमता के परिचायक होंगे। प्रणय सम्बनध मे प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आय–व्यय मे सन्तुलन बनने का प्रयत्न करें। आलस्य का त्याग करें। रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

मकर :– कोई नई जिज्ञासा मन को आकर्षित करेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। शिक्षा–प्रतियोगिता के दिशा में प्ररिश्रम तीव्र होगा। रोजगार में प्रगति संभव। कटु शब्दों का प्रयोग न करें।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर आप उत्साहित होंगे। नियोजित कार्यकुशलता प्रगति के लिए आशान्वित होंगे। सुखद कायरे की व्यस्तता रहेगी। भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी।

मीन :– क्षमता से परे किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना हानिकार हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षा मे लापरवाही ना करें। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।

अरावली बनाम तथाकथित विकास : प्रकृति के शोषण की कीमत

–सुनील कुमार महला

मनुष्य के स्वार्थ और लालच की कोई सीमा नहीं है और आज मनुष्य को विकास के सिवाय जैसे कुछ नज़र ही नहीं आता है, लेकिन विकास के बीच प्रकृति को नजरंदाज करने को क्या ठीक या जायज ठहराया जा सकता है ? अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ ही नहीं है, बल्कि यह तो उत्तर भारत की प्राकृतिक जीवनदृ रेखा है। जहां एक ओर यह मरूस्थल रोकने में ढ़ाल है,जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए वरदान है, वहीं पर दूसरी ओर यह वनस्पतियों, वन्यजीवों, पक्षियों और औषधीय पौधों का प्राकृतिक घर भी है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, जलवायु और वर्षा संतुलन,भूमि क्षरण और बाढ़ नियंत्रण,वायु प्रदूषण से सुरक्षा के साथ ही अरावली कृषि और मानव जीवन का भी प्रमुख आधार है। वास्तव में, यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता के विकास की साक्षी रही है,जिसके संरक्षण में ही मानव, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा निहित है। इसे बचाना केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का भी प्रश्न है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज का मनुष्य स्वयं को विकास की दौड़ में सबसे आगे समझने लगा है, पर यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के नाम पर जंगलों का सफाया, पहाड़ों का कटाव और नदियों का दोहन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर ओर कंक्रीट की ऊँची–ऊँची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। सड़कें, पुल, बांध, सुरंगें और बड़े–बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स इस तरह बनाए जा रहे हैं, मानो प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु हो, संवेदनशील जीवन–तंत्र नहीं। पिछले कुछ समय से देश में खनन के औचित्य और इसके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन यह पूरा मसला विकास बनाम प्रकृति के संरक्षण के द्वंद्व में उलझ कर रह जाता है। आज आदमी को केवल विकास चाहिए, प्रकृति से उसे कोई खास सरोकार नज़र नहीं आता है। विकास की इस अंधी दौड़ में आज वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जबकि वृक्ष ही धरती के फेफड़े हैं। इनके कटने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। मौसम और जलवायु का संतुलन आज बिगड़ चुका है–कहीं असमय बारिश, कहीं भीषण सूखा, तो कहीं विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात सामान्य होते जा रहे हैं।इस तथाकथित विकास का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इससे केवल प्रकृति ही नहीं, बल्कि असंख्य जीव–जंतुओं, वनस्पतियों तथा चरागाहों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जंगल कटने से जानवरों के प्राकृतिक आवास(अधिवास) छिन रहे हैं, जिससे मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। कई प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी हैं, और जैव– विविधता को अपूरणीय क्षति हो रही है।अब यहां यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा विकास टिकाऊ है? क्या वह विकास, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित पर्यावरण न छोड़ सके, सच में विकास कहलाएगा? वास्तव में, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर, पर्यावरण–संरक्षण को केंद्र में रखकर ही सच्चा और स्थायी विकास संभव है।आज मनुष्य को यह समझना होगा कि प्रकृति का शोषण करके वह स्वयं अपने भविष्य को संकट में डाल रहा है। यदि अभी भी चेतना नहीं जागी, तो विकास की यह दौड़ अंततः विनाश की दिशा में ही ले जाएगी। यह बात ठीक है कि आज विकास बहुत जरूरी है, लेकिन अगर विकास के नाम पर प्रकृति को बेधड़क नुकसान पहुँचाया जाए, तो अंत में उसका फायदा किसी को नहीं होगा। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि यह बड़े इलाके और लाखों लोगों के लिए ढाल की तरह काम करती है।मसलन, यह रेगिस्तान को रोकती है, पानी बचाती है(जल संरक्षण और जल पुनर्भरण) और हमारे पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। इसलिए यहां सवाल यह उठता है कि ऐसी जीवन–रेखा को नुकसान पहुँचाने पर समाज को चुप रहना चाहिए या उसके संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए ? पाठक जानते होंगे कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि अरावली पहाड़ी वही मानी जाएगी, जो आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊँची हो। इसका सीधा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि इससे कम ऊँचाई वाले कई क्षेत्र कानूनी तौर पर अरावली के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसी वजह से यह चिंता और बहस तेज हो गई है कि कहीं इस परिभाषा के कारण अरावली के संरक्षण को कमजोर न कर दिया जाए। वास्तव में, अदालत की नई परिभाषा(अरावली) के बाद यह डर पैदा हो गया है कि अगर 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली अरावली की पहाड़ियों में खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिलती है, तो इसका असर सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे अरावली क्षेत्र के पर्यावरण और यहां के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि अरावली को उत्तर भारत के पर्यावरण की प्राकृतिक ढाल माना जाता है, जो मरुस्थलीकरण, जल संकट और जलवायु असंतुलन को रोकती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अरावली क्षेत्र में जिस तरह खनन गतिविधियां बढ़ीं हैं, उससे इसके दुष्परिणाम पहले ही दिखने लगे हैं। हालाँकि, सरकार कह रही है कि खनन केवल 0.19: क्षेत्र तक सीमित रहेगा, पर चिंता यह है कि एक बार खनन की अनुमति मिल गई तो भविष्य में इसका दायरा बढ़ने से कौन रोकेगा? यही इस पूरे कथन की मूल चिंता और संदेश है। बहरहाल, यदि हम यहां इसे सरल शब्दों में समझें तो अरावली पर्वत श्रृंखला को जो नुकसान हुआ है, उसके पीछे मानव स्वार्थ, अव्यवस्थित विकास और सरकारी प्राथमिकताओं की कमी जैसे कई कारण हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली क्षेत्र में खनन, निर्माण, सड़कें, कॉलोनियां और उद्योग तेजी से बढ़े हैं। लोगों ने अपनी सुविधा और तात्कालिक लाभ के लिए पहाड़ियों को काटा, जंगल साफ किए और बड़े पैमाने पर पत्थर व खनिज निकाले। कहना ग़लत नहीं होगा कि इससे अरावली की प्राकृतिक बनावट टूट गई। जब पहाड़ और जंगल खत्म होते हैं तो वे वर्षा जल को रोक नहीं पाते, न ही जमीन के भीतर पानी को जमा कर पाते हैं। शायद इसी का नतीजा है कि आज आसपास के शहरों में, यहां तक कि गांवों तथा ढ़ाणियों तक में भी भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, गर्मी बढ़ रही है और हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती चली जा रही है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर अरावली का संरक्षण क्या इसलिए महत्वपूर्ण नहीं दिखता है,क्योंकि इसके खनन और निर्माण से तुरंत राजस्व, रोजगार और विकास का भ्रम पैदा होता है। वास्तव में सच तो यह है कि दीर्घकालीन पर्यावरणीय नुकसान धीरे–धीरे सामने आता है, इसलिए उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा, अलग–अलग राज्यों की नीतियां, कानूनी उलझनें और शक्तिशाली कारोबारी हित भी संरक्षण के रास्ते में बाधा बनते हैं। अंत में यही कहूंगा कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है। यह थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, वर्षा जल को जमीन में उतारकर भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्यजीवों को आश्रय देती है और करोड़ों लोगों की रोजी–रोटी और जीवन सुरक्षा से जुड़ी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का यह मानना है कि अरावली को आर्थिक लाभ की नजर से नहीं, बल्कि पर्यावरण, जलवायु और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के नजरिये से देखा जाना चाहिए। आज के इस आधुनिक दौर में दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर विकास के नाम पर जो गतिविधियां चल रही हैं, वे कई बार प्रकृति के खिलाफ जाती हैं। वास्तव में,अरावली के मामले में जो भी फैसले या नीतियाँ बनें, उनमें तुरंत मिलने वाला आर्थिक या व्यावसायिक लाभ (जैसे खनन, निर्माण, रियल एस्टेट) को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि हम लंबे समय के पर्यावरणीय नुकसान–जैसे जल संकट, मरुस्थलीकरण, जैव–विविधता का नाश और जलवायु असंतुलन आदि को नजरअंदाज नहीं करके पर्यावरण संरक्षण पर समुचित ध्यान दें।यानी आज का छोटा लाभ भविष्य की बड़ी कीमत पर यदि हासिल किया जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। वास्तव में अरावली के क्रम में यदि समय रहते संतुलित और जिम्मेदार फैसले नहीं लिए गए, तो इसका असर सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर–पश्चिम भारत की जलवायु और जीवन व्यवस्था पर पड़ेगा।इसलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील सोच, जिम्मेदार नीतियाँ और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान आज समय की मांग है।तभी वास्तव में यह धरती(यह नीला ग्रह) और मानव दोनों का अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा।

‘सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की सड़ांध’

–डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा, जो अपने को खेल, सैनिक परंपरा और विकास के दावों के लिए जाना जाता है, वहाँ के सरकारी स्कूलों की जमीनी सच्चाई अक्सर इन दावों से उलट दिखाई देती है। पंचकूला स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में राज्यपाल प्रो. असीम घोष के निरीक्षण के दौरान सामने आई तस्वीर केवल एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की उस सच्चाई को उजागर करती है, जिसे वर्षों से फाइलों और आंकड़ों के पीछे छिपाया जाता रहा है। जब किसी राज्य के राज्यपाल को स्कूल के शौचालयों की दुर्गंध से नाक ढकनी पड़े, तो यह घटना केवल असहजता नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगे प्रश्नचिह्न की तरह देखी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले कुछ वर्षों से "मॉडल संस्कृति स्कूल", "स्मार्ट स्कूल" और "डिजिटल क्लासरूम" जैसे शब्दों के साथ शिक्षा के आधुनिकीकरण के दावे करती रही है। बजट भाषणों में स्कूलों के लिए करोड़ों रुपये की घोषणाएँ होती हैं, नई योजनाओं के पोस्टर लगते हैं और उद्घाटन समारोहों में विकास की तस्वीर पेश की जाती है। लेकिन पंचकूला का यह विद्यालय बताता है कि कागज़ों पर चल रहा विकास ज़मीन पर दम तोड़ रहा है। शौचालयों में पानी नहीं, दरवाज़े टूटे हुए हैं और बुनियादी ढाँचा इस कदर जर्जर है कि कर्मचारियों को सीढ़ियों के अभाव में जुगाड़ से छत पर चढ़ना पड़ता है। यह स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई। यह वर्षों की प्रशासनिक लापरवाही, निरीक्षण तंत्र की विफलता और जवाबदेही के अभाव का परिणाम है। हरियाणा में शिक्षा विभाग की एक पूरी संरचना हैकृब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, इंजीनियरिंग विंग, निरीक्षण समितियाँ और स्कूल प्रबंधन समितियाँ। सवाल यह है कि जब तक राज्यपाल नहीं आए, तब तक किसी को यह दुर्गंध क्यों नहीं आई। क्या ये सभी अधिकारी अंधे थे, या फिर उन्होंने सब कुछ देखकर भी अनदेखा करने को ही अपनी प्रशासनिक संस्कृति बना लिया है। हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच पहले से ही गहरी खाई है, सरकारी स्कूलों की यह हालत सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। जिन परिवारों के पास संसाधन हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज देते हैं। लेकिन जिनके पास विकल्प नहीं, उनके बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में गंदे शौचालय, टूटी इमारतें और असुरक्षित वातावरण केवल अव्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय का रूप ले लेते हैं। शौचालयों की बदहाली को अक्सर एक मामूली समस्या समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह शिक्षा की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। विशेषकर हरियाणा में, जहाँ बालिकाओं की शिक्षा और ड्रॉपआउट दर पहले से ही चिंता का विषय रही है, स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों का अभाव लड़कियों को स्कूल से दूर करने का बड़ा कारण बनता है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की सार्थकता तब सवालों के घेरे में आ जाती है, जब स्कूलों में बेटियों के लिए बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं होतीं। राज्यपाल का आक्रोश स्वाभाविक था और उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश भी दिए। लेकिन हरियाणा का अनुभव बताता है कि ऐसे निर्देश अक्सर तात्कालिक सफ़ाई और लीपापोती तक सीमित रह जाते हैं। कुछ दिनों तक शौचालय चमकते हैं, टूटे दरवाज़े अस्थायी रूप से ठीक कर दिए जाते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यदि इस मामले में भी दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो यह घटना भी बाकी निरीक्षणों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगी। हरियाणा सरकार शिक्षा पर होने वाले खर्च को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन खर्च और परिणाम के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल उठता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। क्या निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, या फिर निगरानी का तंत्र पूरी तरह से ढीला पड़ चुका है। जब तक इन सवालों का ईमानदारी से जवाब नहीं खोजा जाएगा, तब तक किसी भी नई योजना से वास्तविक सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस पूरे प्रकरण में समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हरियाणा में अभिभावक, पंचायतें और स्थानीय जनप्रतिनिधि अक्सर तब तक चुप रहते हैं, जब तक मामला मीडिया में नहीं आ जाता। स्कूल प्रबंधन समितियाँ कागज़ों में तो हैं, लेकिन उन्हें न तो पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और न ही उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। यदि स्थानीय समुदाय स्कूलों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाए, तो ऐसी बदहाली को वर्षों तक छिपाए रखना संभव नहीं होगा। यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बच्चों के लिए सुरक्षा, पोषण और सामाजिक समावेशन का माध्यम भी हैं। मध्याह्न भोजन योजना, स्वास्थ्य जांच और छात्रवृत्तियाँ इन्हीं स्कूलों के ज़रिये पहुँचती हैं। जब स्कूल का माहौल ही असुरक्षित और अपमानजनक हो, तो इन योजनाओं का उद्देश्य भी कमजोर पड़ जाता है। इस घटना को हरियाणा के संदर्भ में एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। सुधार केवल आदेश जारी करने से नहीं होगा। ज़रूरत है कि स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का नियमित स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, निर्माण और रखरखाव से जुड़े ठेकों की पारदर्शी जांच हो, और जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, स्कूल प्रबंधन समितियों और पंचायतों को वास्तविक अधिकार देकर उन्हें जवाबदेही का हिस्सा बनाया जाए। हरियाणा की पहचान मेहनती किसानों, सैनिकों और खिलाड़ियों की भूमि के रूप में रही है। यह राज्य तभी अपनी उस पहचान को कायम रख सकता है, जब उसकी अगली पीढ़ी को सम्मानजनक और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिले। बदबूदार शौचालय, टूटे दरवाज़े और जर्जर भवन किसी भी विकसित राज्य की पहचान नहीं हो सकते। राज्यपाल का रूमाल इस बात का प्रतीक बन गया है कि अब स्थिति छिपाने लायक नहीं रही। यह हरियाणा सरकार, प्रशासन और समाजकृतीनों के लिए आत्ममंथन का क्षण है। यदि इस घटना से सबक लेकर ठोस और स्थायी सुधार किए गए, तो यह निरीक्षण एक सकारात्मक मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन यदि इसे भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद भुला दिया गया, तो यह बदहाली हरियाणा के भविष्य को भी उसी तरह प्रभावित करेगी, जैसे वह आज उसके स्कूलों को कर रही है। अंततः सवाल यही है कि क्या हरियाणा अपने बच्चों को केवल नारों और योजनाओं में "मॉडल" बनाना चाहता है, या वास्तव में उन्हें एक ऐसा स्कूल देना चाहता है, जहाँ स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मान बुनियादी अधिकार हों। शिक्षा की असली कसौटी यही है, और इसी पर राज्य का भविष्य टिका हुआ है।

योगी के ब्राह्मण और ठाकुर विधायक अलग–अलग लामबंद

–संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार छोटी घटनाएं बड़े सियासी बदलावों का संकेत देती हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में हुआ एक सहभोज भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। कुशीनगर से भाजपा विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर 23 दिसंबर की शाम आयोजित इस कार्यक्रम को बाहर से निजी और पारिवारिक बताया गया, लेकिन इसमें शामिल चेहरों, समय और माहौल ने इसे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। सत्र के बीच राजधानी में बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का एक साथ जुटना सामान्य नहीं माना जा रहा। जानकारी के मुताबिक, इस सहभोज में करीब 35 से 40 विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, लेकिन कुछ अन्य दलों के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी सामने आई। मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्र, देवरिया से डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, तरबगंज से प्रेम नारायण पांडेय, बदलापुर से रमेश मिश्र, महनौन से विनय द्विवेदी और एमएलसी साकेत मिश्र जैसे नामों ने बैठक को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया। भोजन में लिट्टी–चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया, जिसे आयोजकों ने सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा से जोड़ा। यूपी विधानसभा में मौजूदा समय में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 बताई जाती है, जिनमें से 46 भाजपा के हैं। यह आंकड़ा खुद में यह बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष में यह समाज कितना प्रभावशाली है। बावजूद इसके, हाल के महीनों में पार्टी के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ती रही है कि संगठन और सरकार में संतुलन बदल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को मिलने के बाद यह भावना और मजबूत हुई कि ब्राह्मण नेतृत्व को अपेक्षाकृत कम अहमियत मिल रही है।उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का इतिहास लंबा और प्रभावशाली रहा है। आजादी के बाद दशकों तक सत्ता की धुरी ब्राह्मण नेतृत्व के इर्द–गिर्द घूमती रही। 1990 के दशक में मंडल राजनीति के उभार के बाद समीकरण बदले, पिछड़ी और दलित जातियों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, लेकिन ब्राह्मण समाज पूरी तरह हाशिये पर नहीं गया। उसने समय–समय पर नए राजनीतिक समीकरणों के साथ खुद को जोड़े रखा। यही कारण है कि आज भी यह समाज भले आबादी में 8 से 10 फीसदी माना जाता हो, लेकिन राजनीतिक असर इससे कहीं ज्यादा रखता है। चुनावी आंकड़े इस प्रभाव को साफ दिखाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का करीब 83 फीसदी समर्थन भाजपा को मिला था। 2022 में यह समर्थन बढ़कर लगभग 89 फीसदी तक पहुंच गया। यानी लगातार दो चुनावों में भाजपा को इस वर्ग से मजबूत समर्थन मिला। प्रदेश की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में ब्राह्मण आबादी 15 फीसदी से अधिक बताई जाती है। ऐसे में लखनऊ की इस बैठक को केवल सामाजिक सहभोज कहना कई लोगों को अधूरा सच लगता है। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह जुटान सिर्फ आपसी मेल–मिलाप थी या इसके पीछे भविष्य की रणनीति भी छिपी है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में खुलकर राजनीति पर तो चर्चा नहीं की गई, लेकिन ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर चिंता जरूर जताई गई। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में सामने आई घटनाओं का जिक्र हुआ, जहां ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय या उपेक्षा की शिकायतें सामने आई थीं। ऐसे मामलों में संगठित होकर प्रतिक्रिया देने और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि बैठक में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने पर भी बातचीत हुई। इसमें वकील, डॉक्टर, रिटायर्ड अधिकारी और समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ने की योजना पर विचार किया गया। मकसद यह बताया गया कि जरूरत पड़ने पर समाज अपने स्तर पर मदद कर सके और किसी पर निर्भर न रहे। इसके साथ ही राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल पर भी चर्चा हुई कि आबादी और योगदान के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।सरकार की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतर्क बयान आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का मिलना–जुलना स्वाभाविक है और इसे जातीय नजरिए से देखना गलत है। उनका कहना था कि विधायक आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं और इसे किसी समुदाय विशेष की बैठक कहना सही नहीं है। सत्ता पक्ष के कई अन्य नेताओं ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने इस बैठक को भाजपा का आंतरिक मामला बताया, लेकिन साथ ही तंज कसने से भी नहीं चूका। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी के भीतर इस तरह की बैठकें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि असंतोष कहीं न कहीं मौजूद है। कुछ नेताओं ने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की बेचैनी के तौर पर देखा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक अपने आप में कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देती है कि जातीय संतुलन का सवाल फिर से केंद्र में आ रहा है। पिछले कुछ समय में ठाकुर समाज और फिर कुर्मी समाज से जुड़े कार्यक्रमों की चर्चा सामने आई थी। उसी क्रम में अब ब्राह्मण विधायकों की यह जुटान देखी जा रही है। यह दिखाता है कि सत्ता के भीतर अलग–अलग सामाजिक समूह अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर सजग हो रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी समय दूर लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैयारियां हमेशा पहले शुरू हो जाती हैं। लखनऊ का यह सहभोज उसी शुरुआती तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा के लिए यह चुनौती है कि वह अपने सबसे मजबूत समर्थक वर्गों में संतुलन बनाए रखे, जबकि विपक्ष के लिए यह मौका है कि वह किसी भी असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करे। फिलहाल, लखनऊ की उस शाम का सहभोज खत्म हो चुका है, लेकिन उससे उठी राजनीतिक चर्चा अभी थमी नहीं है। आने वाले महीनों में अगर ऐसी बैठकों का सिलसिला बढ़ता है, तो साफ हो जाएगा कि यह केवल सामाजिक मेल–मिलाप नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बिसात बिछाने की कोशिश है।

इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो: मुख्यमंत्री

वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए योगी आदित्यनाथ, सिख गुरुओं के अमर बलिदान को किया नमन

सीएम ने साहिबज़ादों के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। धर्म रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर शुक्रवार को आयोजित कीर्तन समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की जो परंपरा स्थापित की, वही हमारी प्रगति का मार्ग है। वीर बाल दिवस के अवसर पर शबद पाठ और कीर्तन समागम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग पर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत में गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने शबद कीर्तन और साहिबज़ादों के अमर बलिदान की गाथा को सुना। कीर्तन पाठ करने वाले बच्चों को पटका पहनाकर और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने 'छोटे साहिबज़ादे' नाम की पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाना, उनके स्वधर्म और स्वदेश के प्रति अमर बलिदान को नमन करने का अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने देशभर के सिख समाज की भावना को स्वीकार करते हुए इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास भारत में भक्ति और शक्ति का इतिहास है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की जो अलख जगाई, उसके प्रचार–प्रसार के लिए देश के कोने–कोने में गए। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने त्याग और बलिदान से इसे अनुकरणीय बनाया। शबद कीर्तन समागम में मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं की परंपरा, उनके त्याग और बलिदान को नमन किया।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का 350वां वर्ष मनाया जा रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कई बार उनके शहीदी दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। यह विशेष संयोग था कि जिस समय हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उसी दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के हर स्कूल, कॉलेज और कार्यालय में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तथा साहिबज़ादों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, ताकि नई पीढ़ी को बलिदान की प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव होता है। सिख धर्म की लंगर परंपरा सामाजिक समरसता का उदाहरण है, जहाँ किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने समाज को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी देवी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस प्रत्येक भारतीय युवा के लिए प्रेरणा का दिन है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के आयोजनों में डबल इंजन सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में आनंद साहिब का पाठ और अरदास हुई। इसके बाद वह मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' एवं असीम अरुण के साथ लंगर में भी सम्मिलित हुए।

भाजपा राज में बाटी-चोखा नहीं, सिर्फ माटी-धोखा मिला : अखिलेश यादव

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं, बल्कि केवल माटी–धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति हाता नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुकी है और उपेक्षा तिरस्कार में बदल चुकी है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज सह नहीं सकता। यादव ने एक्स पर लिखा जब किसी समाज के सामने केवल दो विकल्प सत्ता या सम्मान बचे रह जाते हैं, तब स्वाभिमानी समाज हमेशा सम्मान को ही चुनता है। यह सच्चाई किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि हर वर्ग और समुदाय पर समान रूप से लागू होती है। भाजपा किसी की सगी नहीं है और आज भाजपाई कहलाना एक नकारात्मक सामाजिक पहचान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण जैसी संवेदनशील धरोहरों से खिलवाड़ करते हैं, दोष–सिद्ध अपराधियों को संरक्षण और महिमामंडन देते हैं तथा दवाइयों के नाम पर जहरीली–नशीली चीजें बेचकर लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं में लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नफरत और भय का वातावरण बनाकर समाज को बाँटना, संविधान और कानून के बजाय भीड़ और दबाव की राजनीति करना, तथा वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और कला से डरना,यह सब मौजूदा सत्ता की कार्यशैली को उजागर करता है। उनके अनुसार इसी वजह से अमीर–गरीब की खाई बढ़ी है, बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और महिला, गरीब, वंचित व शोषित वर्गों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि देशभक्त, सभ्य, मानवतावादी, ईमानदार और स्वाभिमानी समाज अब ऐसे राजनीतिक आचरण के साथ खड़ा होकर अपमान और जनाक्रोश का शिकार नहीं होना चाहता। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्ता की इस प्रकार की राजनीति समाप्त नहीं होती, तब तक समाज को बराबरी का सम्मान मिलना संभव नहीं है।

नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 2 माह पहले हुई थी शादी

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र की नई काशीराम कॉलोनी में गुरुवार दोपहर एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, महिला ने फांसी लगाई थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मृतका की पहचान नई काशीराम कॉलोनी, पारा निवासी 22 वर्षीय सामीन पत्नी समीर के रूप में हुई है। उसे अचेत अवस्था में पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ स्थित एरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मलिहाबाद

निवासी सामीन की शादी करीब दो माह पहले 5 अक्टूबर को काशीराम कॉलोनी थाना पारा निवासी समीर से हुई थी। पति समीर वेटर का काम करता है। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलने पर पति मौके पर पहुंचा और पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। मृतका के ससुर जमील और सास रहसून हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के मायके पक्ष को भी सूचित कर दिया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल, मामला संदिग्ध बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

आयुष्मान के भुगतान और शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने मारी बाजी, मिला अवार्ड

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आयोजित नेशनल ग्रीवांस वर्कशॉप में साचीज को मिला सम्मान

जुलाई–25 से अब तक पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना 2200 करोड़ का किया गया भुगतान

मजबूत सॉफ्टवेयर सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता, गंभीर बीमारियों के इलाज पर खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डबल इंजन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB–PMJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश ने एक बार फिर देशभर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश ने योजना के दावों के त्वरित भुगतान, गंभीर बीमारियों के इलाज पर बढ़ते खर्च और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस उपलब्धि के लिए नेशनल ग्रीवांस वर्कशॉप में स्टेट हेल्थ एजेंसी साचीज़ को सम्मानित किया

अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग लाभ उठा रहे साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक कवच के रूप में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष जुलाई 2025 से अब तक प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को लगभग 2200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह भुगतान करीब 1300 करोड़ रुपये था। एक वर्ष के भीतर दावों के भुगतान में लगभग दो गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि न केवल योजना के बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। दावों का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर सीईओ ने बताया कि योगी सरकार ने अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुपूरक बजट में 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी की है। योगी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्वीकृत दावों का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित समय–सीमा के भीतर किया जाए, ताकि निजी और सरकारी अस्पतालों को किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी न हो और मरीजों को निर्बाध इलाज मिलता रहे। ऐसे में भुगतान प्रक्रिया को और अधिक तेज एवं पारदर्शी बनाने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी साचीज़ द्वारा सॉफ्टवेयर सिस्टम को मजबूत किया गया है। साथ ही एजेंसी में कार्यरत कोर टीम की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे दावों की जांच और स्वीकृति में लगने वाला समय कम हुआ है। इसका सीधा लाभ मरीजों और अस्पतालों दोनों को मिल रहा है। गंभीर और उच्च–स्तरीय बीमारियों के इलाज में भी प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है। वर्ष 2024–25 में कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए कुल 894.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक इन सेवाओं के लिए 1370.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अब गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी बड़े और महंगे इलाज तक आसानी से पहुंच बना पा रहे हैं।

गंभीर बीमारियां भी लोगों की पहुंच में साचीज की एसीईओ पूजा यादव ने बताया कि कैंसर (ऑन्कोलॉजी) सेवाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2025द्26 में अब तक ऑन्कोलॉजी सेवाओं के लिए 449.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 285.43 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यमंत्री योगी की उस सोच का परिणाम है, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज को गरीबों की पहुंच में लाने पर विशेष जोर दिया गया है। शिकायतों का निस्तारण भी जल्द से जल्द शिकायत निस्तारण के मामले में भी प्रदेश ने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। जनवरी 2025 से अब तक आयुष्मान योजना के तहत कुल 41,582 शिकायतें और अनुरोध ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हुए। इनमें से 41,458 शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा चुका है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर–25 को आयोजित नेशनल ग्रीवांस वर्कशॉप में स्टेट हेल्थ एजेंसी साचीज़, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। वर्कशॉप में देश के 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ तमिलनाडु, सिक्किम और चंडीगढ़ को भी सम्मान मिला।

फॉर्च्यूनर की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर फरार

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ–रायबरेली हाईवे पर गुरुवार शाम निगोहां के हरवंश खेड़ा नर्सरी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार मजदूर कुलदीप (25) को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि फॉर्च्यूनर डिवाइडर तोड़कर दूसरी पटरी पर चली गयी। गंभीर रूप से घायल कुलदीप को एनएचएआई की एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा तब हुआ जब कुलदीप निगोहां कस्बे से अपनी बाइक से टिकरा गांव स्थित घर लौट रहा था। रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही फॉर्च्यूनर ने मोड़ पर उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। घटना के बाद फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के कारण

लखनऊ–रायबरेली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर निगोहां पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। कुलदीप के निधन की खबर मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। उसके पिता रामसजीवन का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में मां माधुरी, पत्नी ज्योति और दो साल की बेटी काव्या हैं। कुलदीप पांच भाई था। उसके भाई संदीप, सुजीत, सुकेश और दुर्गेश का रो–रोकर बुरा हाल है।

संक्षिप्त

ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया नेशनल वॉलीबॉल चौंपियनशिप का निमंत्रण, 4 जनवरी से वाराणसी में होगी शुरुआत

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्ह चार से 11 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाली नेशनल वॉलीबॉल चौंपियनशिप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री से आत्मीय भेंट कर स्नेहिल सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा उनके बहुमूल्य समय के लिए आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। हाल ही में लखनऊ में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हैं। 23 दिसंबर 2025 को कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई इस बैठक में करीब 40–50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे।

ट्रैफिक डायवर्जन पर पुलिस ने रोका तो कपड़े उतारकर सड़क पर दौड़ी किन्नर हंगामा काटा

संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के कारण शहर में ट्रैफिक डायवर्जन रहा। इसकी वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ा। इस दौरान ट्रैफिक में फंसी एक किन्नर की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। इसके बाद किन्नर ने कपड़े उतार दिए। करीब 15 मिनट तक अर्धनग्न होकर सड़क पर हंगामा काटा। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद वह शांत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचे। वह एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर से प्रेरणा स्थल पहुंचे। शाम करीब 5.00 बजे उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू किया। इस दौरान एसपीजी और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक रोक दिया। प्रेरणा स्थल जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। इस दौरान हुसैनाबाद

स्थित बड़ा इमामबाड़ा के पास भी ट्रैफिक को रोका गया। इससे लोग जाम में फंस गए। इसी ट्रैफिक में एक किन्नर भी फंस गई। काले कपड़े पहने किन्नर एक्टिवा स्कूटी से अपने पुरुष मित्र के साथ कहीं जा रही थी। हुसैनाबाद स्थित बड़ा इमामबाड़ा के पास पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उसे रोक लिया। इस पर किन्नर की पुलिस से नोकझोंक हो गई। इसके बाद गुस्से में किन्नर ने सड़क पर ही एक–एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए और सड़क पर घूमने लगी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे समझाकर शांत कराया।

संक्षिप्त

पुलिस लिखी कार की टक्कर से कारोबारी की मौत, कार छोड़कर ड्राइवर फरार

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस लिखी तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बिजनौर के परवर पश्चिम निवासी अमर सिंह के अविवाहित बेटे अनुराग सिंह के रूप में हुई है। अनुराग टेंट हाउस का कारोबार करता था। गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे वह अपनी बाइक से घर से कुछ दूरी पर स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम कर रहे अपने दोस्त को समोसा देने जा रहा था। घर से थोड़ी दूर सड़क पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने अनुराग के परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन उसे आनन–फानन ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतक अनुराग के परिवार में उसके पिता अमर सिंह, मां पूजा सिंह, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक बहन है। इस मामले में मृतक के पिता अमर सिंह ने बिजनौर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहगीरों से पता चला कि कार चालक काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। कार में 4 लोग सवार थे। कार को मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के डेहवा निवासी जितेंद्र लोधी चला रहा था। घटना के बाद सभी कार छोड़कर सभी फरार हो गए। बाइक में टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे एक दीवार में जा घुसी। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। बिजनौर प्रभारी निरीक्षक कपिल गौतम ने बताया कि मृतक के पिता की ओर से तहरीर मिली है।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल से कार–स्कूटी वाले गमले चुरा ले गए, एफआईआर होगी

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमलों की सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। पुलिस भी तैनात है। लखनऊ विकास प्राधिकरण गमलों को हटवा भी रहा है। बावजूद इसके लोग गमला चुराकर ले जा रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। बच्चे भी गमला चुराकर भाग रहे हैं। हालांकि, पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। किसी को भी गमलों के पास रुकने नहीं दे रही है। दरअसल, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाके को फूलों से सजाया गया।

पीएम के जाने के कुछ घंटे बाद ही लोगों ने सजावट में लगे गमले चोरी कर लिए। मौके पर पुलिसवाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं और मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए। एक गमले की कीमत करीब 100 रुपए बताई जा रही है। 1 महीने पहले सीएम योगी ने जी–20 के बाद चोरी हुए गमलों को लेकर लोगों को चेताया था। कहा था– लोग मर्सिडीज से गमले उठाकर ले गए थे, ऐसी हरकत न करें।

सरकारी स्कूल से आईआईटी बॉम्बे तक उड़ान : संभल के बच्चों ने रचा इतिहास

–योगी आदित्यनाथ की सरकार के एसटीईएम विजन को मिला राष्ट्रीय मंच, निखरीं ग्रामीण प्रतिभाएं

–परिषदीय विद्यालयों के छात्रों ने टेकफेस्ट–2025 में इंजीनियरिंग छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की चुनौती

–कोज्मोक्लेंच और मेसमराइज जैसी जटिल रोबोटिक्स स्पर्धाओं में सहभागिता कर प्रतिभा का मनवाया लोहा

बीएनई

संभल। योगी आदित्यनाथ सरकार की गुणवत्तापरक शिक्षा नीति, एसटीईएम आधारित नवाचार और समान अवसरों के विजन का प्रभाव अब राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। संभल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले परिषदीय पृष्ठभूमि के बच्चों ने वह उपलब्धि हासिल की है, जिसे अब तक बड़े और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों तक सीमित माना जाता रहा है। इन विद्यार्थियों ने प्प्ज ठवउइंल के टेकफेस्ट 2025 में भाग लेकर तकनीकी उत्कृष्टता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है।

योगी सरकार की एसटीईएम विजन को मिला राष्ट्रीय मंच

सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित संभल जनपद के विद्यार्थियों ने एशिया के प्रतिष्ठित विज्ञान एवं तकनीकी महोत्सव टेकफेस्ट 2025 में कोज्मोक्लेंच और मेसमराइज जैसी जटिल रोबोटिक्स स्पर्धाओं में सहभागिता की। कक्षा 4 से 9 तक के इन छात्रों ने देशभर के बीटेक विद्यार्थियों की 250 से अधिक टीमों को सीधी चुनौती दी। उनके तकनीकी कौशल और नवाचार क्षमता से प्रभावित होकर आईआईटी बॉम्बे ने विद्यार्थियों को तकनीकी उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा तथा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि परिषदीय विद्यालयों के छात्र भी उच्च स्तरीय तकनीकी मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इन बच्चों ने रोबोटिक्स जैसी जटिल विधाओं में अपनी दक्षता दिखाई और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के समक्ष कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत की।

प्रशासनिक संबल और गुणवत्तापरक शिक्षा बन रही पहचान

इस सफलता के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार के शिक्षा सुधारों की स्पष्ट भूमिका दिखाई देती है। एसटीईएम शिक्षा पर विशेष फोकस, अवसरों की समानता और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सहयोग ने इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर दिया। जिलाधिकारी डॉ राजेन्द्र पैंसिया के संरक्षण में चयनित 11 मेधावी छात्र, जिनमें बालिकाएं, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल थे, शिक्षक दल के साथ मुंबई पहुंचे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने बताया कि ये विद्यार्थी इससे पहले आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर में भी पुरस्कृत हो चुके हैं। अब आईआईटी बॉम्बे में दो रोबोटिक्स स्पर्धाओं में सम्मान प्राप्त कर संभल ने शिक्षा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा नीति गांव देहात की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफल हो रही है।

नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार

थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

बीएनई

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी, सोनभद्र महोदय के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष शक्तिनगर कमल नयन दूबे के नेतृत्व में दिनांक 26.12.2025 को थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त क्रम में शक्तिनगर पुलिस क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचनाओं की समीक्षा, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अपराध नियंत्रण में लगे हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एम0जी0आर0 बस्ती रेलवे लाइन के पास समय करीब 08:50 बजे एक व्यक्ति को 01 अदद प्लास्टिक के झोले में रखे 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अमित कुमार उर्फ लड्डू पुत्र लक्ष्मण पासवान, निवासी3निमियाडाड बस्ती, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र (स्थायी पता ग्राम फजलगंज, सासाराम, थाना नगर सासाराम, जिला रोहतास, बिहार), उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई है।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना शक्तिनगर पर मु0अ0सं0 218/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष चालान किया गया।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आर्थिक तंगी एवं गलत संगत में पड़ने के कारण वह गांजा बेचकर अपने व अपने परिवार का खर्च चलाता था। आज भी वह गांजा बेचने के उद्देश्य से जा रहा था कि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, किंतु पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण–

अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0–62/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।

मु0अ0सं0–218/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

कमल नयन दूबे, थानाध्यक्ष, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र

उ0नि0 रंजीत कुमार, थाना शक्तिनगर

हे0का0 दिनेश भारती, थाना शक्तिनगर

का0 पंकज कुमार–II, थाना शक्तिनगर

जनपद सोनभद्र पुलिस नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान को निरंतर एवं सख्ती से जारी रखे हुए है। आमजन से अपील है कि नशे से दूर रहें एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

विजन आईएएस पर 11 लाख जुर्माना, परीक्षा परिणामों को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 2022 और 2023 के परिणामों के संबंध में वेबसाइट पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विजन आईएएस (अजय विजन एजुकेशन प्रा.लि.) पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए की आयुक्त व उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया, वेबसाइट पर सीएसई–2023 के लिए लिखा था शीर्ष–10 में 7 और शीर्ष–100 में 79 चयनित। सीएसई–2022 में शीर्ष–50 में 39 छात्र चुने गए थे। इनके साथ सफल उम्मीदवार की फोटो और नाम भी लगाए गए थे। इससे लगता था कि ये सभी टॉपर्स संस्थान के फुल कोर्स वाले छात्र हैं। लेकिन असल में कई तो टेस्ट सीरीज या छोटे कार्यक्रम में थे। जानकारी छिपाई संस्थान ने शुभम कुमार (यूपीएससी सीएसई–2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले) के चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रम अर्थात जीएस फाउंडेशन बैच (कक्षा छात्र) का खुलासा तो किया, पर जानबूझकर अन्य सफल उम्मीदवारों के चुने गए पाठ्यक्रमों की जानकारी छिपा दी। सिर्फ तीन उम्मीदवारों ने लिया दाखिला : सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने यूपीएससी सीएसई–2022 और 2023 में 119 से अधिक सफल उम्मीदवारों का दावा किया था। हालांकि, केवल तीन उम्मीदवारों ने फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लिया था। उपभोक्ता हेल्पलाइन से 42 करोड़ वापस मिले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद से अप्रैल से दिसंबर के बीच 30 क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 42.6 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाई गई है।

संक्षिप्त

चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में जापान! 58 अरब डॉलर के रक्षा बजट को दी मंजूरी; बनाया ये रिकॉर्ड

एजेंसी

टोक्यो। जापान के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आगामी वर्ष के लिए 9 ट्रिलियन येन (58 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा के रक्षा बजट को मंजूरी दी। इस रिकॉर्ड रक्षा बजट योजना का मकसद इलाके में बढ़ते तनाव के मद्देनजर क्रूज मिसाइलों और मानवरहित हथियारों के साथ अपनी जवाबी हमला करने की क्षमता और तटीय रक्षा को मजबूत करना है। अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बजट का मसौदा 2025 की तुलना में 9.4 प्रतिशत ज्यादा है। यह जापान के चल रहे पांच वर्षीय कार्यक्रम का चौथा वर्ष है जिसका उद्देश्य वार्षिक हथियार खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक दोगुना करना है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बड़ा फैसला रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब जापान को चीन से बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

रिटर्न देने में ब्लूचिप शेयरों से इस साल पिछड़ गए मिड-स्मॉलकैप शेयर, पहले दिया था भारी-भरकम मुनाफा

एजेंसी

नई दिल्ली। बीएसई सेंसेक्स के इस पूरे कैलेंडर साल में 9 फीसदी का फायदा देने के बीच मिड और स्मॉलकैप शेयरों ने निवेशकों को निराश किया है। हालांकि, ब्लूचिप यानी बड़े शेयरों ने अच्छा रिटर्न दिया। विश्लेषकों के मुताबिक, मिड और स्मॉलकैप शेयरों में इसलिए कम फायदा मिला, क्योंकि 2023 और 2024 में इन दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था।विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर की तुलना में रुपये में भारी गिरावट, अमेरिका–भारत व्यापार वार्ता को लेकर चिंताओं और लगातार विदेशी निधियों की निकासी ने भी बाजार में जोखिम से बचने की योजना को बढ़ावा देने में मदद की। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मॉलकैप और मिडकैप सूचकांकों का दृष्टिकोण सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है। जैसे–जैसे मूल्यांकन कम होगा और आय की स्पष्टता में सुधार होगा, भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था वृद्धि और मजबूत घरेलू तरलता के समर्थन से चुनिंदा अवसर उभरेंगे। स्मॉलकैप से घाटा मिडकैप से सिर्फ 0.77 फीसदी रिटर्न 24 दिसंबर तक बीएसई मिडकैप सूचकांक में सिर्फ 360.25 अंकों या 0.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में 3,687 अंकों या 6.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसी दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स 7,269.69 अंकों या 9.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्थानीय निवेशकों का लक्ष्य छोटे शेयरों पररू छोटे शेयरों को स्थानीय निवेशक खरीदते हैं। विदेशी निवेशक ब्लू–चिप या बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब बाजार में समय के साथ बदलाव होता है, जैसा कि सितंबर, 2024 से हो रहा है, तो छोटे और मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन आमतौर पर कम रहता है। इस लिहाज से इस वर्ष सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में छोटे और मिडकैप शेयरों का कम प्रदर्शन आश्चर्यजनक नहीं है।

सचिन भी कम उम्र में खेले थे.., वैभव सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई से श्रीकांत की बड़ी मांग

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई से बड़ी अपील की है। श्रीकांत का मानना है कि जिस तरह सचिन तेंदुलकर को कम उम्र में भारतीय टीम में मौका दिया गया था, उसी तरह वैभव सूर्यवंशी को भी जल्दी सीनियर सेटअप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने वैभव की उम्र से ज्यादा उसकी प्रतिभा, निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को प्राथमिकता देने की बात कही। रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से मची हलचल वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा जब वह लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में उन्होंने मात्र 84 गेंदों पर 190 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 छक्के लगाए और सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और चयनकर्ताओं के सामने एक मजबूत दावा पेश किया। हर स्तर पर रन, हर फॉर्मेट में असर श्रीकांत वैभव की निरंतरता से खासे प्रभावित हैं। युवा स्तर से लेकर घरेलू क्रिकेट तक, वैभव ने लगातार बड़े स्कोर किए हैं। 15 यूथ वनडे मैचों में वैभव सूर्यवंशी का औसत 51.13 का है, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 158.79 का रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और आधुनिक क्रिकेट की समझ को दर्शाता है। श्सचिन भी इतनी ही उम्र में खेले थे श्रीकांत ने वैभव को और इंतजार कराने की सोच को सिरे से खारिज किया और सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए चयनकर्ताओं से साहसिक फैसला लेने की अपील की। उन्होंने अपने यूट्यूब चौनल 'चीकी चाका' पर कहा, श्वैभव हर जगह शतक बना रहा है, चाहे वह आईपीएल हो, अंडर–19 हो या कोई और स्तर। आप कह सकते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है, लेकिन वह अलग बात है। लड़के में जबरदस्त क्षमता है श्रीकांत ने कहा, श्यह लड़का हर तरह के मैचों में हर किसी की धज्जियां उड़ा रहा है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि उसे टी20 वर्ल्ड कप के लिए फास्ट–ट्रैक किया जाना चाहिए। शायद अब उसके लिए देर हो गई हो, लेकिन फिर भी उसे टीम में जल्दी लाया जाना चाहिए। इस लड़के में जबरदस्त क्षमता है और उसे जल्द भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए।

विजय की 'जन नायकन' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में मलेशियाई पुलिस ने लगाई पाबंदियां, समारोह में नहीं कर सकेंगे ये काम

एजेंसी

अभिनेता से राजनेता बने तमिल सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चाओं में हैं। हालांकि, हिंदी में इस फिल्म को 'जन नेता' के नाम से रिलीज किया जाएगा। शनिवार यानी 27 दिसंबर को फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट होना है। बड़े पैमाने पर होने वाला यह इवेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में अभिनेता विजय समेत फिल्म की पूरी कास्ट के मौजूद रहने की संभावना है। अब इस इवेंट से पहले मलेशियाई पुलिस ने कुछ कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। जानिए किन बातों पर पुलिस ने लगाया प्रतिबंध... राजनीतिक गतिविधियों पर पूरा प्रतिबंध 'जन नायकन' के भव्य ऑडियो लॉन्च इवेंट से पहले मलेशियाई पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है। मलेशियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल मलेशिया पुलिस ने 'जन नायकन' केल कार्यक्रम में राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके तहत इवेंट के दौरान राजनीतिक भाषणों या राजनीतिक प्रतीक का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चेरास जिला पुलिस प्रमुख सहायक आयुक्त ऐदिल बोलहसन ने कहा कि अनुमति केवल एक एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए दी गई है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक संदेश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रतिबंध राजनीतिक अभिव्यक्ति के सभी रूपों पर लागू होता है, जिसमें भाषण, प्रतीक, बैनर, सामग्री, आंदोलन, काफिले और संगीत कार्यक्रम स्थल या उसके आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक संदेशों का सीधा प्रसारण शामिल है। भारी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद देश में 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से इन प्रतिबंधों के पालन करने की बात कही गई। कार्यक्रम दिए गए नियमों का पालन करेगा और यह पूरी तरह से एक मनोरंजन से भरपूर इवेंट रहेगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है, क्योंकि इवेंट और ऑडियो लॉन्च में 90,000 फैंस के शामिल होने की उम्मीद है। विजय की 69वीं फिल्म है 'जन नायकन' एच विनोथ द्वारा निर्देशित जन नायकन थलापति विजय की 69वीं फिल्म है। यह फिल्म पोंगल के अवसर पर 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। यह विजय की राजनीति में प्रवेश करने से पहले उनकी आखिरी फिल्म बताई जा रही है। इस फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह बना हुआ है।

एक जैसी हुडी पहने दिखाई दिए रश्मिका मंदाना–विजय देवरकोंडा, न्यू ईयर 2026 मनाएंगे एक साथ

एजेंसी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को हाल ही में एक जैसी हुडी पहने हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान दोनों को एक जैसे कपड़े पहने देखकर उनकी डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल गई है। एक साथ मनाएंगे न्यू ईयर इंडिया टुडे की एक खबर के अनुसार, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए एक साथ छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। वे हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। विजय ने ग्रे कलर की हुडी और अपनी पसंदीदा बीनी कैप पहनी थी, जबकि रश्मिका ब्लैक आउटफिट में थीं। रश्मिका और विजय का लुक रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एयरपोर्ट से अपनी एक फोटो शेयर की और लिखा, अब छुट्टियों का समय!श उन्होंने लाल दिल वाले और गले लगाने वाले इमोजी भी लगाए। छुट्टी पर पहुंचकर रश्मिका ने एक बड़े क्रिसमस ट्री के पास अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं। वे मजेदार पोज दे रही थीं और कैप्शन में लिखा, मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे दोस्तों। फैंस ने नोटिस किया कि रश्मिका की हुडी विजय की पुरानी हुडी से मिलती–जुलती है, जो वे अक्सर पहनते हैं। एक फैन ने कमेंट किया, विजय कहां है?, तो दूसरे ने कैप की तरफ इशारा किया। अक्सर चर्चा में रहते हैं रश्मिका और विजय रश्मिका और विजय की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अक्तूबर 2025 में सगाई कर ली है और फरवरी 2026 में शादी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743